स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई के लिये उत्तराखंड की नदियों के जल का उपयोग

3013. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र की नदियों के जल का उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंचाई के लिये उन नदियों के जल का उपयोग करने का है;

(ग) क्या उत्तराखण्ड की जनता को केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो वहां सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र की नदियों का जल लघु सिंचाई कार्यों में तकनीकी दृष्टि से सम्भव मात्रा तक उपयोग में लाया जा रहा है । उत्तराखण्ड की भौगोलिक दशाओं के अन्तर्गत मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती है ।

(ख) जी हां । राज्य सरकार भविष्य में इन नदियों के और अधिक जल का उपयोग करना चाहती है ।

(ग) जी नहीं । सीमित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है ।

(घ) चौथी योजना के दौरान इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये 70 लाख रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है । इस रकम में इस क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लम्बी सिंचाई की नालियों का निर्माण करना भी शामिल है ।

Allocation of Non-Ferrous Metals for Industries

3014. SHRI TRIDIB CHAUDHURY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the principles on which the allocation of non-ferrous metals required for different industries as raw materials is made ;

(b) whether any attempt has been made to maintain some proportionality between their actual requirements and the allocations ;

(c) the steps Government propose to take for removing the existing disparities in the allocation of these metals as between different States and their requirements calculated on the basis of their installed capacities ; and

(d) the arrangement made for scrutinising the various claims for allocation, State-wise and industry-wise ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI KUMARAMANGALAM) : (a) The existing units engaged in the Priority industries are allocated non-ferrous metals on replenishment basis, partly from indigenous production and partly from imports, keeping in view the licensed capacity and the estimated demand of the end product.

In the case of non-priority industries, the allocation of non-ferrous metals is made on the basis of past production, consumption of imported non-ferrous metals during the previous year and generally not exceeding the licensed/approved capacity of each unit.

(b) Yes, Sir.